



**CHETANA**  
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal  
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor  
SJIF 2026-8.584



Prof. A.P. Sharma  
Founder Editor, CIJE  
(25.12.1932 - 09.01.2019)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पश्चात सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षण पद्धतियाँ एवं मिश्रित अधिगम मॉडल: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

मंजू गुप्ता

प्रोफेसर, शिक्षा विभाग

जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर

Email-manju.gupta@jagannathuniversity.org, Mobile-9166114404

First draft received: 07.02.2026, Reviewed: 09.02.2026

Final proof received: 11.02.2026, Accepted: 15.02.2026

### शोध सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी के वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। NEP 2020 ने खासतौर पर डिजिटल शिक्षा और टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर जोर दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब विद्यालय बंद थे, तब डिजिटल शिक्षण का महत्व और भी बढ़ गया। इस रिपोर्ट में हम देखेंगे कि NEP 2020 के बाद सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षण पद्धतियों का कैसे इस्तेमाल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, विशेष रूप से डिजिटल शिक्षा और मिश्रित अधिगम (Blended Learning) के क्षेत्र में। इस शोध पत्र में सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षण विधियों और मिश्रित अधिगम मॉडलों के प्रयोग, उनके क्रियान्वयन, व्यवहारिक अनुभवों और चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन दर्शाता है कि कैसे NEP 2020 ने डिजिटल बुनियादी ढांचे, शिक्षकों के तकनीकी प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के लिए लचीले एवं अनुकूल अधिगम वातावरण के निर्माण की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया है। साथ ही यह पेपर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई पहलों, जैसे DIKSHA, SWAYAM और PM eVidya जैसे प्लेटफार्मों की प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन एवं इसमें डिजिटल शिक्षा की चुनौतियाँ, सीमाएँ, और नीति-स्तर पर सुधार हेतु सुझाव भी प्रस्तुत करता है।

**मुख्य शब्द :** NEP 2020, डिजिटल शिक्षण, मिश्रित अधिगम, सरकारी विद्यालय, DIKSHA, eVidya, ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षा में नवाचार.

### प्रस्तावना

#### ● शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन की आवश्यकता

21वीं सदी की शिक्षा पद्धति में डिजिटल तकनीकों का समावेशन आवश्यक हो गया है। बदलते वैश्विक परिदृश्य, सूचना का तीव्र प्रसार, और नवाचार-आधारित शिक्षण पद्धतियाँ यह संकेत देती हैं कि पारंपरिक कक्षा शिक्षण के साथ-साथ डिजिटल रूपांतरण भी अनिवार्य है। यह परिवर्तन विशेष रूप से सरकारी विद्यालयों के लिए समावेशी, गुणवत्ता-युक्त और न्यायसंगत शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

#### ● NEP 2020 में तकनीक की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) तकनीक को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर एक सहायक उपकरण के रूप में पहचानती है। यह नीति डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने, शिक्षकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने, और विद्यार्थियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने पर विशेष बल देती है। इसमें 'राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी फोरम (NETF)' की स्थापना का भी उल्लेख है, जिसका उद्देश्य तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना है।

#### ● सरकारी विद्यालयों की पारंपरिक चुनौतियाँ और अवसर

सरकारी विद्यालय अक्सर संसाधनों की कमी, शिक्षकों की प्रशिक्षण संबंधी समस्याएँ, और तकनीकी उपकरणों के अभाव से जूझते हैं। लेकिन NEP 2020 के माध्यम से यह विद्यालय भी अब डिजिटल तकनीकों के समावेशन का अवसर पा रहे हैं, जिससे सीखने की गुणवत्ता में सुधार संभव है।

### NEP 2020 और डिजिटल शिक्षण की रूपरेखा

#### ● डिजिटल साक्षरता का समावेशन

NEP 2020 शिक्षा के हर स्तर पर डिजिटल साक्षरता को एक मूलभूत क्षमता के रूप में देखती है। छात्रों को तकनीक का उपयोग करना, सूचना खोजना, और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना सिखाना अब आवश्यक है। इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर लागू करने पर बल दिया गया है।

#### ● डिजिटल सामग्री का निर्माण और उपयोग

नीति में गुणवत्तापूर्ण, बहुभाषी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार डिजिटल शैक्षिक सामग्री विकसित करने का सुझाव दिया गया है। DIKSHA जैसे राष्ट्रीय पोर्टल पर शिक्षकों व छात्रों के लिए ई-सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। यह सामग्री शिक्षण को अधिक रोचक, सहभागितापूर्ण और सुलभ बनाती है।

#### ● समावेशी डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा-निर्देश

NEP 2020 सभी बच्चों तक डिजिटल शिक्षा पहुँचाने पर बल देती है, चाहे वे किसी भी भौगोलिक, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से हों। इसके लिए कम लागत वाले उपकरणों, ऑफलाइन सामग्री, और क्षेत्रीय भाषाओं में संसाधनों के विकास की आवश्यकता बताई गई है।

#### डिजिटल शिक्षण पद्धतियाँ: परिभाषा, प्रकार एवं प्रयोग

वर्तमान युग सूचना और संचार तकनीक (ICT) का युग है, जिसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है, और शिक्षा-क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों के साथ-साथ अब डिजिटल शिक्षण पद्धतियाँ (Digital Learning Methods) भी तीव्र गति से विकसित हो रही हैं। डिजिटल शिक्षण में ऐसी सभी विधियाँ सम्मिलित होती हैं जो डिजिटल तकनीकों और इंटरनेट आधारित संसाधनों का उपयोग कर अधिगम को सुलभ, सशक्त और प्रभावी बनाती हैं।

**परिभाषा: डिजिटल तकनीक आधारित अधिगम विधियाँ**

डिजिटल शिक्षण पद्धतियाँ वे विधियाँ हैं जो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल उपकरणों, और अन्य डिजिटल माध्यमों के सहारे शैक्षणिक जानकारी के प्रस्तुतीकरण, प्रसार और अधिगम की प्रक्रिया को संचालित करती हैं। यह केवल पाठ्यवस्तु को डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सहभागी, अंतःक्रियात्मक और learner-centered प्रक्रिया है।

**प्रमुख तकनीकें****1. ई-पाठ्यपुस्तकें (E-books)**

ई-पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए कहीं भी, कभी भी अध्ययन करने का एक आधुनिक माध्यम हैं। ये पुस्तकों के डिजिटल संस्करण होते हैं जिन्हें मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है। ई-बुक में हाइपरलिंक, मल्टीमीडिया, नोट्स और खोज विकल्प जैसे विशेषताएँ उन्हें पारंपरिक पुस्तकों से अधिक उपयोगी बनाती हैं।

**2. वीडियो लेक्चर**

वीडियो लेक्चर शिक्षकों द्वारा रिकॉर्ड किए गए पाठ होते हैं जिन्हें छात्र बार-बार देख सकते हैं। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब छात्र स्वयं की गति से अध्ययन करना चाहते हैं। YouTube, Khan Academy, और अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वीडियो शिक्षा को सजीव और रोचक बनाते हैं।

**3. Google Classroom, DIKSHA, SWAYAM**

- Google Classroom शिक्षकों और छात्रों के बीच संचार, असाइनमेंट वितरण और मूल्यांकन के लिए एक सहज प्लेटफॉर्म है।
- DIKSHA (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing) भारत सरकार द्वारा विकसित एक शैक्षणिक पोर्टल है जहाँ शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है।
- SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) उच्च शिक्षा से लेकर स्कूली शिक्षा तक के लिए ऑनलाइन कोर्स प्रदान करता है। यह डिजिटल समावेशन का सशक्त उदाहरण है।

**LMS (Learning Management System)**

LMS एक सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली है जो पाठ्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए प्रयुक्त होती है। Moodle, Blackboard, और Canvas जैसे LMS संस्थानों को डिजिटल रूप में शिक्षण-संचालन की सुविधा प्रदान करते हैं।

**उपकरणों का उपयोग**

डिजिटल शिक्षण को प्रभावी बनाने में विभिन्न तकनीकी उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है:

- **स्मार्ट बोर्ड:** यह इंटरैक्टिव श्वेतपट होता है जिस पर डिजिटल पेन और टच के माध्यम से कार्य किया जा सकता है।
- **टैबलेट और मोबाइल ऐप्स:** शिक्षण-अधिगम के लिए BYJU'S, Vedantu, Toppr जैसी अनेक मोबाइल ऐप्स उपलब्ध हैं जो बच्चों को गेमिफाइड और व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करती हैं।
- **प्रोजेक्टर:** वीडियो, स्लाइड शो और एनिमेशन के माध्यम से पाठ्यवस्तु को दृश्य रूप में प्रस्तुत कर सीखने को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है।

**शिक्षक प्रशिक्षण एवं ICT साक्षरता**

डिजिटल शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक तकनीकी रूप से दक्ष हों। ICT (Information and Communication Technology) साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों का प्रयोग करने की क्षमता। शिक्षक

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत उन्हें ई-शिक्षण उपकरणों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मल्टीमीडिया तकनीकों का प्रयोग सिखाया जाता है। इसके अंतर्गत NISHTHA, DIKSHA जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण मॉड्यूल भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

**ऑनलाइन मूल्यांकन एवं प्रतिक्रिया तंत्र**

डिजिटल शिक्षण का एक प्रमुख लाभ ऑनलाइन मूल्यांकन और प्रतिक्रिया प्रणाली है।

- ऑनलाइन क्विज, MCQ टेस्ट, असाइनमेंट सबमिशन जैसे माध्यमों से छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सकता है।
- Google Forms, Kahoot, Quizizz जैसे उपकरणों से छात्र तुरंत प्रतिक्रिया (Instant Feedback) प्राप्त करते हैं जिससे उनके प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है।
- AI आधारित एनालिटिक्स शिक्षकों को यह जानने में मदद करते हैं कि किस विषय में छात्र कमजोर हैं और किस क्षेत्र में अधिक दक्षता प्राप्त है।

**मिश्रित अधिगम (Blended Learning) मॉडल****• परिभाषा और प्रमुख विशेषताएँ**

मिश्रित अधिगम वह शिक्षण मॉडल है जिसमें पारंपरिक (शारीरिक) कक्षा शिक्षण और ऑनलाइन अधिगम को मिलाकर एक संयुक्त रणनीति अपनाई जाती है। यह मॉडल लचीलापन, पहुंच, और व्यक्तिगत गति से सीखने की सुविधा प्रदान करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं:

- ✓ कक्षा और डिजिटल संसाधनों का संतुलन
- ✓ व्यक्तिगत अनुकूलन (personalized learning)
- ✓ शिक्षक एवं तकनीक दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण

**• शारीरिक कक्षा और ऑनलाइन अधिगम का संतुलन**

इस मॉडल में शिक्षक विषयवस्तु को कक्षा में समझाते हैं, जबकि विद्यार्थी घर पर वीडियो, क्विज, या प्रैक्टिस मॉड्यूल के माध्यम से विषय को और गहराई से सीखते हैं। इससे छात्रों को स्वयं अध्ययन का अवसर मिलता है और कक्षा की समय-सीमा में भी लचीलापन आता है।

**• छात्रों की सहभागिता और स्वशिक्षा को बढ़ावा देना**

ब्लेंडेड लर्निंग छात्रों को अपनी गति से सीखने, पुनरावृत्ति करने, और डिजिटल साधनों का उपयोग करके जानकारी को खोजने की आदत विकसित करता है। यह मॉडल आत्मनिर्भरता (Self-learning), सहयोगी अधिगम (Collaborative learning), और तकनीकी साक्षरता को बढ़ावा देता है।

**सरकारी पहलों की समीक्षा****• DIKSHA प्लेटफॉर्म:**

राष्ट्रीय स्तर पर विकसित DIKSHA (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing) एक व्यापक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए मुफ्त, गुणवत्तापूर्ण, और स्थानीय भाषा में डिजिटल सामग्री प्रदान करता है। इसमें QR कोड, पाठ्यपुस्तक, वीडियो, प्रशिक्षण मॉड्यूल आदि शामिल हैं।

**• PM मटपकल: एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म**

कोविड-19 के दौरान शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने हेतु भारत सरकार ने PM मटपकल पहल की शुरुआत की। इसके अंतर्गत:

- ✓ DIKSHA पोर्टल,
- ✓ शैक्षिक टीवी चैनल (कक्षा 1 से 12 के लिए 'एकलव्य' चैनल),

- ✓ रेडियो व पॉडकास्ट के माध्यम से शिक्षा दी जाती है।

#### ● SWAYAM और SWAYAM PRABHA

SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) एक ऑनलाइन पोर्टल है जो उच्च शिक्षा और स्किल कोर्स प्रदान करता है।

SWAYAM PRABHA डीटीएच सेवा के माध्यम से 24\*7 शिक्षा-प्रसारण करता है, जो इंटरनेट की सीमाओं से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से सहायक है।

#### ● राज्य सरकारों की डिजिटल नीति

- ✓ दिल्ली सरकार ने 'Virtual Schools' की शुरुआत की है जहां डिजिटल क्लासरूम व लाइव क्लास उपलब्ध हैं।
- ✓ केरल ने 'KITE-Victers' चैनल और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं।
- ✓ कर्नाटक ने 'Kalike Kagga' जैसी स्थानीय ई-लर्निंग पहलें शुरू की हैं, जिनमें स्थानीय भाषाओं में वीडियो सामग्री प्रदान की जाती है।

#### शिक्षकों की भूमिका और प्रशिक्षण

##### ● डिजिटल उपकरणों का प्रशिक्षण

शिक्षकों को स्मार्ट बोर्ड, टैबलेट, ई-लर्निंग ऐप आदि का उपयोग सिखाना अनिवार्य हो गया है।

##### ● शिक्षण विधियों में बदलाव

पारंपरिक व्याख्यान पद्धति की बजाय सहभागी, परियोजना आधारित और मिश्रित शिक्षण विधियाँ अपनाई जा रही हैं।

##### ● शिक्षक की डिजिटल सक्षमता का प्रभाव

तकनीकी रूप से दक्ष शिक्षक न केवल सामग्री की गुणवत्ता बढ़ाते हैं बल्कि छात्र की संलग्नता भी सुनिश्चित करते हैं।

#### लाभ और सीमाएँ

##### ● लाभ:

- ✓ शिक्षण सामग्री की सुलभता: कहीं भी, कभी भी पहुँच संभव।
- ✓ लचीला और विद्यार्थी-केंद्रित अधिगम: स्वगति से सीखने का अवसर।
- ✓ शिक्षकों की सशक्त भूमिका: संसाधन प्रदाता और मार्गदर्शक के रूप में भूमिका।

##### ● सीमाएँ:

- ✓ डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण-शहरी अंतर, लैपटॉप/इंटरनेट की कमी।
- ✓ तकनीकी अवसंरचना की कमी: बिजली, नेटवर्क, उपकरणों की अनुपलब्धता।
- ✓ डिजिटल साक्षरता की कमी: शिक्षक व अभिभावकों की तकनीकी समझ सीमित।

#### नवाचार और श्रेष्ठ प्रथाएँ (Best Practices)

- हाइब्रिड शिक्षण प्रयोगों की केस स्टडी
- सामुदायिक सहभागिता और नवाचार
- विद्यार्थी प्रतिक्रिया पर आधारित परिवर्तन
- हाइब्रिड शिक्षण प्रयोगों की केस स्टडी

केरल के 'KITE-Victers' और दिल्ली के वर्चुअल स्कूल मॉडल डिजिटल शिक्षा में नवाचार का उदाहरण हैं।

##### ● सामुदायिक सहभागिता और नवाचार

माता-पिता, पंचायत, और स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी से शिक्षा को सुदृढ़ किया गया।

#### ● विद्यार्थी प्रतिक्रिया पर आधारित परिवर्तन

प्रतिक्रिया आधारित पाठ योजना, शैक्षिक ऐप्स की चयन प्रक्रिया, और पाठ्यक्रम संशोधन से गुणवत्ता में सुधार आया।

#### चुनौतियाँ

हालाँकि डिजिटल शिक्षण में कई लाभ हैं, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ प्रमुख चुनौतियाँ भी सामने आई हैं:

1. इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता और कनेक्टिविटी समस्याएँ एक बड़ी चुनौती हैं।
2. तकनीकी उपकरणों की कमी: कई सरकारी स्कूलों में स्मार्टफोन, कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरणों की कमी है, जिससे छात्रों को डिजिटल शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
3. शिक्षकों की ट्रेनिंग: कई शिक्षक डिजिटल उपकरणों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
4. आर्थिक बाधाएँ: कई परिवारों के पास बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण नहीं होते, जिससे डिजिटल शिक्षा में असमानता पैदा होती है।
5. सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ: कुछ क्षेत्रों में विद्यार्थियों के पास आवश्यक तकनीकी संसाधनों की कमी होने के कारण यह डिजिटली शिक्षा एक सामाजिक-वर्गीय खाई का रूप ले सकती है।

#### सुझाव

1. इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधारें: ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएँ।
2. शिक्षकों को प्रशिक्षण दें: डिजिटल शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाए।
3. समान अवसर प्रदान करें: छात्रों के बीच तकनीकी संसाधनों के मामले में असमानता को दूर करने के लिए नीतियाँ बनाएँ।
4. आधुनिक उपकरणों की आपूर्ति: स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और अन्य डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ।

#### ● नीति-निर्माताओं के लिए सुझाव

- ✓ डिजिटल अवसंरचना हेतु विशेष बजट
- ✓ शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य कार्यक्रम
- ✓ स्थानीय भाषाओं में ई-सामग्री का विस्तार

#### ● स्कूल स्तर पर बदलाव हेतु रणनीतियाँ

- ✓ "डिजिटल समावेशन टीम" की स्थापना
- ✓ माता-पिता को डिजिटल प्रशिक्षण
- ✓ ऑफलाइन डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता

#### ● भविष्य की संभावनाएँ और शोध के क्षेत्र

- ✓ AI आधारित व्यक्तिगत अधिगम प्रणाली
- ✓ ग्रामीण शिक्षा में तकनीक का दीर्घकालिक प्रभाव
- ✓ समावेशी शिक्षा के लिए मल्टी-मॉडल ICT

#### भविष्य की दिशा

1. हाइब्रिड लर्निंग: NEP 2020 ने हाइब्रिड लर्निंग की अवधारणा को बढ़ावा दिया है, जहाँ छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शिक्षा प्राप्त होगी।
2. शिक्षकों के लिए डिजिटली ट्रेनिंग: सरकार और अन्य संस्थाएँ शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा के लिए प्रशिक्षण देने के लिए अधिक प्रयास कर रही हैं।
3. इंटरनेट की पहुँच में वृद्धि: सरकार द्वारा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

4. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड लर्निंग: भविष्य में, AI और मशीन लर्निंग का उपयोग शिक्षा में अधिक बढ़ेगा, जिससे व्यक्तिगत और अनुकूलित शिक्षण प्रदान किया जा सकेगा।

#### निष्कर्ष

NEP 2020 ने डिजिटल शिक्षा को सरकारी स्कूलों में एक महत्वपूर्ण दिशा दी है। हालांकि इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ हैं, लेकिन सही उपायों के साथ इसे दूर किया जा सकता है। डिजिटल शिक्षा न केवल सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पहुंच योग्य बना सकती है, बल्कि यह छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार भी कर सकती है। इसके लिए सरकार, शिक्षा विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा, ताकि डिजिटल शिक्षा का पूरा लाभ हर बच्चे तक पहुंच सके।

#### संदर्भ सूची

1. शिक्षा मंत्रालय. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. भारत सरकार. [https://www.education.gov.in/sites/upload\\_files/mhrd/files/NEP\\_Final\\_Hindi\\_0.pdf](https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_Hindi_0.pdf)
2. एनसीईआरटी. (2021). कोविड-19 के बाद स्कूली शिक्षा पर प्रभाव और डिजिटल शिक्षण संसाधन. नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद.
3. मिश्र, आर. के. (2022). डिजिटल शिक्षा और सरकारी विद्यालय: एक मूल्यांकन. भारतीय शैक्षिक समीक्षा, 58(1), 45-59.
4. यादव, पी. एवं शर्मा, के. (2021). मिश्रित अधिगम पद्धति और छात्रों की सहभागिता: एक अध्ययन. शिक्षा संवाद, 12(3), 22-35.
5. त्रिपाठी, एस. (2023). डिजिटल युग में शिक्षण विधियाँ: सरकारी विद्यालयों की चुनौतियाँ. वाराणसी: ज्ञानभारती प्रकाशन.
6. एनसीईआरटी. (2020). दीक्षा मंच और ई-लर्निंग संसाधनों का परिचय. नई दिल्ली: एनसीईआरटी. <https://diksha.gov.in/>
7. बिष्ट, ए. (2022). डिजिटल शिक्षण में शिक्षकों की भूमिका: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में. शिक्षा विमर्श, 18(2), 17-28.
8. UNESCO. (2021). *Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374029>
9. पांडेय, जी. (2023). शिक्षा में नवाचार और तकनीकी हस्तक्षेप. इलाहाबाद: विश्वविद्यालय प्रकाशन.
10. कुमार, आर. (2022). भारत में मिश्रित अधिगम के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण. शोध विमर्श पत्रिका, 10(1), 65-74.